फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 252 प्रभात जयपुर, गुरूवार 16 अप्रैल, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

# राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

**English Is Not English** — The most transformative event in the history of the English language occurred in 1066 with the Norman Conquest...

**The "Black Death" of the African Savannah**

**The Great Drama** — Indian vs. Western Theatre - A Human Drama, the other is a living art

# राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया विपक्ष ने

## मुद्दा था, संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र, जो सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए आहूत किया है

- विपक्ष की बैठक में राहुल ने पुरजोर तरीके से कहा कि विपक्ष के सभी सांसद उपस्थित होने चाहिए, संसद में जब सरकार विधेयक को पारित करने के बहाने, संसदीय सीटों का परिसीमन करना चाहती है।
- तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने कहा, तृणमूल के सभी सांसद उपस्थित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प.बंगाल में चुनाव चल रहे होंगे।
- डी.एम.के. सांसद बालू, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में पार्टी के नेता संजय सिंह, शिव सेना के नेता उद्धव ठाकरे, जो विपक्ष की बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए थे, एक स्वर में राहुल गांधी की बात का पुरज़ोर समर्थन किया और तृणमूल के प्रतिनिधि पर पूरा दबाव बनाया कि तृणमूल के सभी सांसद, विशेष सत्र में उपस्थित होने चाहिए। क्योंकि भाजपा को घेरना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर भाजपा की मनमानी बेरोकटोक चलती रही तो प्रजातंत्र ही खतरे में आ जाएगा और चुनाव भी बेमायने हो जाएंगे।
- राहुल के नेतृत्व को शायद पहले विपक्ष का पूर्ण समर्थन कभी नहीं मिला है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की एक बैठक में, तृणमूल कांग्रेस की प्रतिनिधि और सांसद सागरिका घोष ने कहा कि चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सभी सांसद संसद में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि केवल 5 से 7 सांसद ही मौजूद रह सकें।

इस पर आहत राहुल गांधी ने कहा कि यदि विपक्षी दलों के सभी सांसद नहीं आएंगे, तो यह संसद में भाजपा की मदद करने के बराबर होगा।

राहुल गांधी का समर्थन करते हुए, द्रमुक के टी.आर. बालू ने कहा कि तमिलनाडु में भी चुनाव हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी के सभी सांसद संसद में बहस में हिस्सा लेने और अपनी आवाज़ उठाने के लिए उपस्थित रहेंगे। "आप" के सांसद और राज्यसभा नेता संजय सिंह ने इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सांसद उपस्थित हों।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा चुनावों से बड़ा है और अगर स्थिति ऐसी ही रही, तो लोकतंत्र ही अर्थहीन हो जाएगा और चुनाव बेकार हो जाएंगे।

शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, जो बैठक में ऑनलाइन जुड़े थे, ने कहा कि वे ममता बनर्जी से बात करेंगे और उनकी पार्टी के सभी सांसदों की संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देंगे।

अन्य उपस्थित लोगों ने भी यही भावना व्यक्त की और सभी ने उम्मीद जताई कि तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सभी सांसद इस मुद्दे पर भाजपा को परास्त करने के लिए संसद में उपस्थित होंगे।

# अदालत ने सुबोध अग्रवाल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

जयपुर, 15 अप्रैल। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

एसीबी की ओर से रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को सुबोध अग्रवाल को अदालत में पेश किया गया। एसीबी की ओर से कहा गया कि अभी तक आरोपी से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में उसकी रिमांड अवधि को दो दिन और बढ़ाया जाए। इसका विरोध

- जलजीवन मिशन घोटाले के आरोपी अग्रवाल ने खतरे की आशंका जताते हुए अलग सेल में रखने की प्रार्थना की।

करते हुए सुबोध अग्रवाल के वकील ने कहा कि उन्होंने एसीबी के सवालों का जवाब दे दिया है। ऐसे में उन्हें जेल भेजा जाए। इसके साथ ही, उन्होंने जेल में खतरा बताकर अन्य कैदियों से अलग सेल में रहने की गुहार की। सुनवाई के दौरान सुबोध अग्रवाल ने कहा कि एसीबी अधिकारी मीडिया को कह रहे हैं कि उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, बताइए उन्होंने किन सवालों के जवाब नहीं दिए। गौरतलब है कि एसीबी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक और भेजे

## वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, ये दस हजार सैनिक गल्फ क्षेत्र में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों को जॉइन करेंगे

- विशेषज्ञों के अनुसार, एक तरफ तो अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है, दूसरी तरफ अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, इससे ऐसा लगता है कि सीज़फायर, जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है, के बाद संघर्ष और लंबा खिंच सकता है।
- ट्रंप, ईरान युद्ध के बारे में परस्पर विरोधाभासी बयानबाजी करते रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा, मुझे लगता है, यह (युद्ध) जल्दी ही खत्म हो जाएगा, पर, अगले बयान में उन्होंने कहा, विश्व अगले दो दिनों में भारी सैन्य बल तैनाती देखेगा।
- वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, 6,000 सैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यु बुश व उसके साथ के जहाजों से लिए गए हैं तथा 4,200 सैनिक बॉक्सर एम्फीबियस रैडी ग्रुप व इलैवन्थ मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट से लिए गए हैं।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान में युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही, पेंटागन की योजना के अनुसार, अस्थायी युद्धविराम के 22 अप्रैल को समाप्त होने से ठीक पहले, मध्य पूर्व में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं। संकेत स्पष्ट हैं: जहाँ ट्रम्प युद्ध के जल्द खत्म होने की बात कर रहे हैं, वहीं वॉशिंगटन इस संभावना के लिए तैयारी कर रहा है कि संघर्ष और लंबा और गंभीर हो सकता है।

ट्रम्प अपने युद्ध संबंधी बयानों में विरोधाभासों को लेकर लगातार विवादित रहे हैं। उन्होंने हाल ही में फॉक्स न्यूज़ को कहा, "मुझे लगता है कि यह (संघर्ष) बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा।" एक अन्य बयान में उन्होंने कहा, "दुनिया अगले दो दिनों में तेजी से होते घटनाक्रम की गवाह बनेगी।"

"वॉशिंगटन पोस्ट" की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 6,000 सैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश और उसके एस्कॉर्ट जहाजों पर हैं, जबकि अन्य 4,200 सैनिक बॉक्सर एम्बीशियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट से हैं। ये अतिरिक्त सैनिक लगभग 50,000 अमेरिकी कर्मियों के साथ शामिल होंगे, जो पहले से ही खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं। मध्य पूर्वी जल क्षेत्रों में तीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी मौजूद हैं।

इस समय, अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रहा है, तथा ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोत कई जहाजों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की ज़ैड प्लस सुरक्षा वापस ली

## राघव की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिसकर्मियों को तुरंत हैड क्वार्टर रिपोर्ट करने को कहा गया है

- साफ जाहिर है कि आप नेतृत्व और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच कटुता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप नेतृत्व का आरोप है कि राघव संसद में प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रभावी तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और अपने व्यक्तिगत प्रचार में लगे हुए हैं। हालांकि राघव ने इन आरोपों का खंडन किया है।
- इसी वजह से पहले उन्हें राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटाया और अब ज़ैड प्लस सुरक्षा भी छीन ली गई।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता पद से हटाए जाने के कुछ ही दिन बाद, पंजाब सरकार ने आज सांसद को दी गई ज़ैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली।

37 वर्षीय चड्ढा की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को तुरंत मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

यह कार्यवाही आप और उसके पंजाब सांसद के बीच तेजी से बढ़ते और कटु होते मतभेदों के बीच की गई है।

आप ने चड्ढा पर आरोप लगाया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार के खिलाफ संसद में अपनी आवाज उठाने से बचते रहे और इसके बजाय "सॉफ्ट पीआर" में लगे रहे। इसी कारण पार्टी ने 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया।

चड्ढा ने पार्टी के आरोपों को "झूठ" करार देते हुए कहा कि वे संसद में लोगों के मुद्दे उठाने जाते हैं, हंगामा करने के लिए नहीं।

# सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आरएएस हनुमाना राम को जमानत नहीं दी

जयपुर, 15 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर दो उम्मीदवारों के स्थान पर परीक्षा देने वाले निलंबित आरएएस हनुमाना राम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस

- अदालत ने कहा कि आरएएस होते हुए भी डमी अभ्यर्थी बनने वाले को जमानत नहीं मिल सकती।

सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश आरोपी हनुमाना राम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पर तीन व्यक्तियों के लिए डमी अभ्यर्थी बनने का आरोप है। यह एक घटना नहीं है, बल्कि आरोपी के निरंतर आचरण को दर्शाती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली ट्रांज़िट बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

## सुप्रीम कोर्ट बैंच ने कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा व अन्य को नोटिस जारी किया और असम सरकार की याचिका पर जवाब देने को कहा

- कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां पर तीन देशों के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था, जिस पर रिंकी ने उन पर एफआईआर की थी।
- पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए भारी मात्रा में असम पुलिस बल ने दिल्ली में खेड़ा के आवास पर दबिश की थी। असम के मुख्यमंत्री के इस प्रतिकारी एक्शन के कारण पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेनी पड़ी।
- तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ट्रांज़िट बेल दी थी, अर्थात इस अवधि में उन्हें असम की अदालत से जमानत लेनी ही होगी।
- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और ए.एस. चन्दुरकर की बैंच ने कहा, अगर खेड़ा असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो यह रोक अप्रभावी हो जाएगी।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को एक हफ्ते के लिए ट्रांज़िट अग्रिम जमानत दी गई थी। यह जमानत असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिन्की भुइयां सरमा द्वारा दर्ज एफआईआर से संबंधित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं।

न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि यदि कांग्रेस नेता उपयुक्त अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो इस रोक का उन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा और न ही कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालेगा।

पीठ ने पवन खेड़ा और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है, और असम सरकार की हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उनके जवाब मांगे हैं।

# विश्व बैंक ने राजस्थान को 2,000 करोड़ रूपए दिए

जयपुर, 15 अप्रेल। विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ एग्ज़ीक्युटिव डायरेक्टर्स ने राजस्थान में राज्य राजमार्गों की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा सुधार के लिए 225 मिलियन डॉलर (लगभग 2 हजार करोड़ रुपये) से अधिक की

- यह राशि राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के तहत 800 किमी सड़कों के उन्नयन व रखरखाव के लिए दी गई है।

राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। विश्व बैंक के अनुसार, इस परियोजना से औद्योगिक, खनन, पर्यटन और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी का लाभ भी मिलेगा।

यह परियोजना राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को आधुनिक और सेवा केन्द्रित बनाने में मददगार साबित होगी। इससे प्राधिकरण प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर के चयनित राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव करेगा। साथ ही, राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा। इस स्वीकृत प्रोजेक्ट से भारत में पहली बार स्टेप-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# अमेरिका के ब्लॉकेड के प्रत्युत्तर में ईरान ने भी "काउन्टर ब्लॉकेड" की धमकी दी

## अगर ईरान अपनी धमकी के अनुरूप "रेड सी" से ब्लॉक कर देता है, इस पूरे इलाके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकदम ठप्प हो जाएगा

- चीन व रूस भी इस ब्लॉकेड प्रकरण में ईरान के साथ हैं तथा अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा हैं।
- हताश होकर, अमेरिका ईरान से दोबारा वार्ता शुरु करना चाहता है, जिससे दो सप्ताह की "सीज़फायर" की अवधि कुछ और समय तक बढ़ाई जा सके।
- ट्रंप ने अपने आप एक तरफा घोषणा कर दी है कि वार्ता शुरु हो रही है।
- ट्रंप इस्लामाबाद में वार्ता करना चाहते हैं, पर, दूसरा पक्ष यूरोप में किसी सैन्ट्रल स्थान पर वार्ता आयोजित करना चाहता है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। अमेरिकी सरकार द्वारा होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी पर गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए, ईरान ने पश्चिम में लाल सागर से लेकर पूर्व में ओमान की खाड़ी तक विस्तृत जल क्षेत्र में जवाबी अवरोध की धमकी दी है। यदि यह प्रभावी ढंग से किया गया, तो इससे पूरे क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है, जिनमें यूरोप-एशिया मार्ग के लिए स्वेज नहर का उपयोग करने वाले जहाज भी शामिल हैं।

ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच, अमेरिका खुद को पूरी तरह कूटनीतिक संकट में पा रहा है। रूस और चीन भी इसमें शामिल हो रहे हैं और अमेरिका को और अधिक अलग-थलग करने के प्रयास कर रहे हैं।

स्पष्ट संकेत हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के साथ दो सप्ताह की युद्धविराम अवधि बढ़ाने और होर्मुज़ स्ट्रेट की नौवहन सुविधा पर गतिरोध को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से वार्ता फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है।

ट्रम्प ने एकतरफा तौर पर ईरान के साथ संवाद फिर से शुरू करने की संभावनाओं की घोषणा की है, ताकि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वार्ता पुनः शुरू की जा सके। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान का परमाणु मुद्दे पर प्रस्ताव और होर्मुज़ स्ट्रेट को पुनः खोलने का प्रस्ताव, अन्य कारणों के साथ, वार्ता को रोक रहा था।

डॉनल्ड ट्रम्प जोर दे रहे हैं कि वार्ता इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होनी चाहिए, जबकि कुछ अन्य पक्ष सुझाव दे रहे हैं कि इसे ऐसे स्थान पर किया जाए जो ज्यादा केन्द्रीय क्षेत्र, जैसे कि यूरोप के किसी स्थान, में आयोजित किया जाना चाहिए। स्थान परिवर्तन से संभवतः अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व की संभावना बन सकती है।

विडंबना यह है कि सबसे बड़ी अड़चन है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो, केवल उन शर्तों को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो जेसीपीओए ढांचे के तहत पहले ही प्राप्त हो चुकी थीं।

जेसीपीओए समझौता, जो प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ था, डॉनल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद ईरान ने जेसीपीओए समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं से बाहर निकलते हुए एक मजबूत परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, जिससे परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने की संभावना बढ़ गई।

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद वार्ता कई मुद्दों पर अटकी हुई थी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम भी शामिल था। वार्ता विफल होने के बाद, अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की घोषणा की, जिससे यहाँ जहाजों की आवाजाही प्रभावी रूप से रोक दी गई। इस जलमार्ग से तेल का परिगमन लगभग रुक गया।

इससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगा, जो होर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से तेल की आवाजाही पर बहुत ज्यादा निर्भर भारी निर्भर थीं, जिनमें चीन और अधिकांश एशियाई देश शामिल हैं। नाकेबंदी की अमेरिका की घोषणा की चीन ने "खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना" करार देते हुए कड़ी निंदा की।

वास्तव में, अनुमान के अनुसार, चीन अपना 40 प्रतिशत तेल ईरान से लेता है, और चीन अपनी रणनीतिक तेल भंडार में गंभीर कमी से आशंकित है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# सीबीएसई के कक्षा दस के नतीजे घोषित

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को कक्षा 10 की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष कुल 93.70 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

- छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा 94.99 प्रतिशत छात्राएं तथा 92.69 प्रतिशत छात्र पास हुए।

हुए, जो पिछले वर्ष के 93.66 प्रतिशत की तुलना में 0.04 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्शाता है।

बोर्ड के अनुसार, इस वर्ष 24,83,479 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 24,71,777 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए और 23,16,008 छात्र-छात्राएं सफल घोषित किए गए। परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक किया गया था। क्षेत्रवार प्रदर्शन में, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा क्षेत्र 99.79

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)